the following steps have been taken to meet the situation.

(i) Development of varieties of crops plants specially suited for export purposes such as basmati rice, durum wheat etc.

(ii) Development of varieties of maize for industrial uses such as starch and other products which have export value.

(iii) Research on 'OO' varieties of Rapseed and Mustard for export potential of quality oilmeal.

(iv) Work on bio-technology is being intensified in the area of Molecular Biology and Plant Cell Culture for crop improvement.

(v) Development of technology and equipment for reduction of post harvest losses, value-additional of farm produce, agro-waste and by product utilization as well handling and processing of cotton, jute and other fibres for high quality yarn and product and also their by-product utilization.

(v) Collection, evaluation, cataloguing and conservation of germplasm.

समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाएं

709. **श्री दिग्विजय सिंह:**
श्री सत्यप्रकाश मालवीय:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी संस्थायें कार्यरत हैं और वर्ष 1994 तक ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी थी एवं वर्ष 1994-95 में कितनी और संस्थाएं शुरू की गई या की जाने वाली हैं;

(ख) समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं को सरकार द्वारा मंजूरी देने संबंधी मानदण्ड क्या हैं और इस परियोजना के अन्तर्गत किस-किस प्रकार की सेवायें प्रदान की जाती हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओं के कार्यकरण का सर्वेक्षण किया जाता है; यदि हां, तो वर्ष 1993-94 में संस्थाओं के कार्यों का ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार चालू वित्त वर्ष में कोई और समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है, इन परियोजनाओं पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी और इन परियोजनाओं से क्या लाभ होने की आशा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवराजेश्वरी): (क) अद्यतन स्थिति के अनुसार, देश में 3908 आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें से 3342 परियोजनाएं पूरी तरह से कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त 31-3-94 तक 3378 आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी थीं। इसके अलावा, 1994-95 के दौरान, 255 और आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

(ख) आई० सी० डी० एस० स्कीम के अन्तर्गत समुदाय विकास ब्लाकों का चयन अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अधिकतम प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का आनुपातिक हिस्सा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाली ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बाहुल्य वाले समुदाय विकास ब्लाकों को प्रथम वरीयता प्रदान की जाती है। आई० सी० डी० एस० स्कीम के तहत, कमजोर वर्गों जिनमें 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती तथा शिशुवती माताएं भी शामिल हैं, को पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरोधन, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं तथा पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा आदि समेकित सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) विभाग ने आई० सी० डी० एस० स्कीम के कार्यान्वयन का प्रबोधन करने के लिए एक प्रबन्ध सूचना प्रणाली विकसित की है। आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर, विभाग तिमाही प्रगति रिपोर्टें तैयार करता है, जिनका स्कीम के तहत लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने हेतु नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर राज्यों से उपचारात्मक उपाय करने हेतु नियमित रूप से कहा जाता है। 31-3-94 की स्थिति के अनुसार, लगभग 76.50 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्र

स्कीम के मापदण्ड के अनुसार पूरक पोषाहार उपलब्ध करवा रहे थे। शेष 23.50 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्र माह में 1-21 दिन की रेंज में पोषाहार उपलब्ध करवा रहे थे।

(घ) सरकार आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ स्कीम को यथाशीघ्र सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। चालू वर्ष के दौरान, लगभग 460 नई आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। उक्त भाग (ख) में उल्लिखित पिछड़ेपन के मानदण्ड के आधार पर नए ब्लाकों का पता लगाया जायेगा। देश में आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ परियोजनाएं स्वीकृत करने का उद्देश्य कमजोर वर्गों के पोषाहार तथा स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाना है।

Introduction of mother tongue as medium of teaching in primary schools

710. SHRI MOOLCHAND MEENA:
SHRI SANJAY DALMIA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have formulated some directives regarding the introduction of mother tongue as the medium of teaching in primary schools;

(b) whether any guidelines have been issued to the State Governments in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (c) The Policy of the government, in regard to medium of instruction at the primary stage is set out in Article 350 A of the Constitution and the National Policy on Education, 1986.

Covering new districts under Total Literacy Campaign

711. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the criteria for selecting new districts for Total Literacy Campaign;

(b) the details of the new districts selected in different States and Union Territories for the purpose;

(c) whether Government propose to launch this campaign in each and every district in the country; and

(d) if so, the steps taken by Government in that direction?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) The project proposals for total literacy campaign are prepared in the districts by the Zilla Saksharata Samitis based on the criteria like educational resources available in the districts, level of preparedness for launching literacy campaign, the commitment of the State and district administration and creation of a demand for literacy generated through multi-media publicity leading to mass mobilisation.

The proposals from districts, as recommended by the State Governments, are initially scrutinised and are followed by pre-launch appraisal visits of a team of the National Literacy Mission representatives for reporting on the state of preparations made in the districts for launching of literacy campaigns. Based on the appraisal report, the district proposals are considered in the periodic meetings of the Project Approval Committee of the National Literacy Mission Authority.

(b) to (d) The objective of the National Literacy Mission is to cover 100 million persons in 345 districts of the country by the end of the Eighth Five-Year Plan. The Total Literacy Campaign has become